

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग-1

देहरादून दिनांक: 20 जुलाई, 2007

विषय:- वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्षक संख्या-3456 के अन्तर्गत वचनबद्ध मदों में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-599/XXVII(1)/2007, दिनांक 12 जुलाई, 2007 तथा शासनादेश संख्या- 287/XIX/बजट/07-42/खाद्य/2007, दिनांक 03 अप्रैल, 2007 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 03 अप्रैल, 2007 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 में लेखानुदान के अन्तर्गत दिनांक 01 अप्रैल, 2007 से 31 जुलाई, 2007 तक के लिये स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्षक-3456 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में वचनबद्ध मदों के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्नक में उल्लिखित मानक मदों के विवरणानुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन धनराशि रु. 1,16,71,000.00 (रुपये एक करोड़ सौलह लाख इकत्तर हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वहन पर रखते हुए व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए अधिकृत धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजना पर ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नई मदों के क्रियान्वयन के लिए नहीं किया जायेगा।
- 2- स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्तीय हस्तापुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेज रूल्स एवं मितव्ययता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जायेगा।
- 3- यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय नहीं किया जायेगा जिसके लिए वित्तीय हस्तापुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो, उस प्रकरण में व्यय के पूर्व यह प्राप्त कर ली जाय।
- 4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का समय से उपयोग करने के लिये यह सुनिश्चित करें, कि धनराशियों को परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दिया जाय तथा व्यय का विवरण यथा समय प्रत्येक माह बी0एम-13 पर शासन को उपलब्ध कराया जाय।
- 5- समस्त चालू निर्माण कार्य, मशीनों, उपकरण एवं संयंत्र तथा वाहन आदि के कय तथा अवचन मदों पर धनराशि के व्यय हेतु शरान की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6- आवश्यक मदों हेतु आवश्यकानुसार स्वीकृति के लिए प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

7- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-3456-सिविल पूर्ति-00-आयोजन-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित निदेशालय की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र जोशी)
सचिव।

संख्या-595 (1)/XIX/बजट/07-43/खाद्य/2007, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-


- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, औबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
- 2- आयुक्त कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
- 3- आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- अध्यक्ष, समस्त जिला फोरम उपभोक्ता संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 7- निबन्धक, राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 8- वरिष्ठ सम्भागीय वित्त अधिकारी, खाद्य, गढ़वाल/कुमायूँ संभाग, देहरादून/हल्द्वानी।
- 9- सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गढ़वाल/कुमायूँ संभाग, देहरादून/हल्द्वानी।
- 10- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्य, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 11- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 12- वित्त अनुभाग-5/खाद्य अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
- 13- समन्वयक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(ओ0पी0तिवारी)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या- 595 /XIX/07-43/2007, दिनांक 20 जुलाई, 2007 का संलग्नक।

अनुदान संख्या-25	(धनराशि हजार रू० में) आयोजनेत्तर
लेखाशीर्षक-3456-सिविल पूर्ति	
001-निदेशन तथा प्रशासन	
04-उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित निदेशालय	
01-वेतन	4950
02-मजदूरी	6
03-महंगाई भत्ता	2970
06-अन्य भत्ते	600
09-विद्युत देय	50
10-जलकर/जल प्रभार	20
13-टेलीफोन पर व्यय	300
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	200
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	100
48-महंगाई वेतन	2475
योग- (एक करोड सौलह लाख इकत्तर हजार मात्र)	11671


(ओ०पी०तिवारी)
उप सचिव।